भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1349

08.12.2025 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण कम करने के उपाय

1349. **श्री विजय कुमार हाँसदाक :**
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के कई शहर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं;

(ख) देश भर के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों का राज्य-वार सं.रा. क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक शहर में प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है/कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि गंभीर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को काफी खतरा है और आर्थिक लागत बढ़ जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने प्रदूषण के स्तर को काफी कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनी विभिन्न योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) : वायु प्रदूषण के प्रभाव के संबंध में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए हैं।

वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले एवं दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए एक दीर्घकालीन, समयबद्ध, राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) की शुरुआत की है।

सभी 130 शहरों द्वारा एनसीएपी के तहत अपनी-अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित उपायों के क्रियान्वयन के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं के तहत वायु प्रदूषण के स्रोतों यथा मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों से होने वाले

उत्सर्जन, कचरे को जलाना, निर्माण और विध्वंस संबंधी गतिविधियों तथा औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित किया गया है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों में से दस लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों/शहरी समूहों का पंद्रहवें वित्त आयोग मिलियन प्लस शहरी चुनौती निधि के तहत वायु गुणवत्ता कार्य-निष्पादन अनुदान के रूप में वित्तपोषण किया जाता है तथा शेष 82 शहरों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रदूषण नियंत्रण स्कीम के तहत वित्तपोषित किया जाता है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 से अब तक महत्त्वपूर्ण अंतर वित्तपोषण के अंतर्गत 130 शहरों के लिए एनसीएपी के तहत 13,415 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।
इसके अलावा, एनसीएपी स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, पीएम ई-ड्राइव, सतत (एसएटीएटी) जैसी केन्द्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों के संसाधनों के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा नगर पालिका और शहरी विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियों के संसाधनों को एकीकृत कर संसाधनों को जुटाने पर बल देता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग अपने-अपने बजट के अनुसार अपनी स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण करते हैं।

*****